vinetur

पोलैंड ने छोटी शराब की बोतलों पर शुल्क चार गुना करने का प्रस्ताव रखा

प्रस्ताव के तहत पूरी आय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष को मिलेगी। सालाना प्राप्तियां लगभग 560 मिलियन ज़्लॉटी से बढ़कर 1.5 बिलियन ज़्लॉटी होने की उम्मीद है।

सोमवार, 23 नवंबर 2026



पोलैंड की सरकार छोटी शराब की बोतलों की बिक्री पर लगने वाले विशेष शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर रही है। योजना के तहत पूरी आय देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को दी जाएगी। इससे लोकप्रिय छोटी बोतलों की कीमतें बढ़ेंगी, जबकि स्थानीय सरकारों की आमदनी घटेगी।

प्रस्ताव में तथाकथित małpkowe शुल्क में बदलाव किया जाएगा। इसका नाम małpki से आया है—वोदका की वे छोटी बोतलें, जो आम तौर पर 100-मिलीलीटर और 200-मिलीलीटर आकार में बिकती हैं। मसौदे के मुताबिक, पूरी आय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष को मिलेगी, जिसे पोलिश संक्षिप्त नाम NFZ से जाना जाता है। फिलहाल यह रकम कोष और नगरपालिकाओं के बीच बांटी जाती है।

यह कदम NFZ के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की सरकार की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। कोष पर भारी वित्तीय दबाव है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ मौजूदा खर्चों के लिए ही इसके पास 10 बिलियन ज़्लॉटी से अधिक की कमी है। 2026 की दूसरी तिमाही में दी गई उन स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान का निपटारा भी अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिन पर खर्च की कोई

सीमा नहीं है। अस्पतालों ने भर्ती सीमित कर दी है, कुछ मरीजों को दूसरे केंद्रों में भेजा है और कई अन्य को बहुत आगे की तारीखें दी हैं।

सरकार ने उस अलग वेतन कानून में बदलाव नहीं किया है, जो स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी की गारंटी देता है, हालांकि इस कानून को कोष के बढ़ते घाटे का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके बजाय, वित्त मंत्रालय ने शराब की बिक्री से जुड़ी सीमित दायरे वाली राजस्व योजनाओं का समर्थन किया है।

इनमें से एक उपाय पहले ही आगे बढ़ चुका है। शराब पर उत्पाद शुल्क में 20% की बढ़ोतरी करने वाले एक पुराने कानून पर राष्ट्रपति Karol Nawrocki ने November 18 को हस्ताक्षर किए थे। इस बढ़ोतरी से NFZ को 1.4 बिलियन ज़्लॉटी अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है। अब सरकार का अनुमान है कि małpkowe शुल्क में बढ़ोतरी से भी लगभग इतनी ही, या इससे अधिक, रकम आएगी।

मसौदे में बताए गए उद्देश्य के अनुसार, अतिरिक्त धन से शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों, मनोरोग देखभाल, लत के उपचार और शराब से होने वाले नुकसान से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को वित्तपोषित करने में मदद मिलेगी। अपने प्रभाव आकलन में सरकार का तर्क है कि शराब का सेवन लत का एक बड़ा जोखिम है। उसका कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति व्यक्ति शराब सेवन संबंधी आंकड़ों में पोलैंड दुनिया में 12वें स्थान पर है। इसी आकलन के मुताबिक, पोलैंड में शराब अब भी बहुत सस्ती है और अत्यधिक सेवन को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में कीमतें बढ़ाना शामिल है—खासकर युवाओं और सबसे अधिक शराब पीने वालों के बीच।

सरकार ने शराब की बढ़ती सामर्थ्य का भी हवाला दिया है। उसका कहना है कि 2021 में, जब छोटी बोतलों पर यह शुल्क लागू हुआ था, औसत मासिक वेतन से 841 छोटी बोतलें खरीदी जा सकती थीं। 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,026 हो गई।

मसौदे में प्रस्तावित बढ़ोतरी काफी बड़ी है। 100-मिलीलीटर की वोदका बोतल की कीमत में małpkowe शुल्क अभी 1 ज़्लॉटी है। इसे बढ़ाकर 4 ज़्लॉटी किया जाएगा। 200-मिलीलीटर की बोतल पर शुल्क अभी 2 ज़्लॉटी है, जिसे बढ़ाकर 8 ज़्लॉटी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि छोटी बोतलों की बिक्री में एक-चौथाई की गिरावट की उम्मीद है, फिर भी ऊंची दर के कारण कर राजस्व में बड़ी वृद्धि का अनुमान है। इस शुल्क से मौजूदा सालाना आय 560 मिलियन से 590 मिलियन ज़्लॉटी आंकी गई है। बढ़ोतरी के बाद सरकार को इसके 1.5 बिलियन ज़्लॉटी तक पहुंचने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, मसौदे का अनुमान है कि नए नियम लागू होने के बाद परिवारों का शराब पर खर्च 1.1 बिलियन ज़्लॉटी से अधिक बढ़ेगा। इससे आलोचना तेज हुई है कि यह कदम शराब का सेवन घटाने के बजाय बजट की कमी पूरी करने के लिए उठाया जा रहा है। Polish Network of Economics की विशेषज्ञ Maria Libura ने इसे पाप-कर का एक पारंपरिक उदाहरण बताया और कहा कि राज्य को शराब की लत में भारी कमी लाने पर ध्यान देना चाहिए, उससे मुनाफा कमाने पर नहीं। NFZ के पूर्व प्रमुख Andrzej Sośnierz ने तर्क दिया कि अगर छोटी बोतलें बहुत महंगी हो गईं, तो कुछ उपभोक्ता कम पीने के बजाय बड़ी बोतलों की ओर लौट सकते हैं।

इस संभावित बदलाव का असर कर नीति से भी आगे तक जा सकता है। यूरोप के एक अहम स्पिरिट्स बाजार में डिस्टिलर, वितरक और खुदरा विक्रेताओं के लिए आकार के आधार पर लगाया गया ऊंचा शुल्क कीमतों की संरचना बदल सकता है, मुनाफे का मार्जिन घटा सकता है और पैकेजिंग संबंधी फैसलों को प्रभावित कर सकता है—खासकर यदि उपभोक्ता छोटी बोतलों से बड़ी पैकिंग की ओर रुख करें।

प्रस्ताव से यह भी बदलेगा कि रकम किस तरह बांटी जाती है। सरकार का कहना है कि नगरपालिकाओं ने शुल्क से मिले अपने हिस्से का इस्तेमाल हमेशा लत की रोकथाम और शराब से होने वाले नुकसान को घटाने के लिए नहीं किया है। मसौदे के तर्क के अनुसार, स्थानीय सरकारों के पास 2025 में लगभग 77 मिलियन ज़्लॉटी खर्च नहीं हुए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ नगरपालिकाओं ने यह धन शराब नीति से केवल ढीले तौर पर जुड़ी गतिविधियों पर खर्च

किया—जैसे मेले, खेल और मनोरंजन कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नृत्य कक्षाएं, यहां तक कि कूड़ेदानों की खरीद और स्थापना। हालांकि, मसौदे में नशामुक्ति केंद्रों, हस्तक्षेप केंद्रों और हेल्पलाइन पर हुए खर्च को भी स्वीकार किया गया है।

małpkowe से होने वाली आय के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार शराब बिक्री लाइसेंस शुल्क बढ़ाने की योजना बना रही है। लेकिन नगरपालिकाओं को इससे लगभग 150 मिलियन ज़्लॉटी अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है—छोटी बोतलों के शुल्क से उन्हें फिलहाल मिलने वाली रकम का करीब आधा। इस पर स्थानीय अधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि लत का इलाज, समुदाय स्तर पर किए जाने वाले रोकथाम के काम की जगह नहीं ले सकता।

Union of Polish Cities ने कहा कि स्थानीय रोकथाम के लिए धन में कटौती से सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे आगे चलकर स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सहायता व्यवस्थाओं पर और अधिक दबाव पड़ेगा। Association of Polish Counties के विशेषज्ञ Marek Wójcik ने कहा कि इस प्रस्ताव से NFZ के बजट में केवल मामूली फर्क पड़ेगा, लेकिन नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति पर इसका बड़ा असर होगा। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि मसौदे से शराब बिक्री परमिटों को लेकर प्रशासनिक बोझ काफी बढ़ेगा और कुछ प्रस्तावित नियम अस्पष्ट होने के कारण कारोबारियों के साथ लंबे कानूनी विवाद हो सकते हैं।

वामपंथी दल के सीनेटर और पूर्व उप स्वास्थ्य मंत्री Wojciech Konieczny, जिन्होंने पोलैंड के संयम कानून में बदलावों पर काम किया था, ने कहा कि उनकी पार्टी का अपना स्वास्थ्य कर प्रस्ताव है, जिसके तहत शराब और तंबाकू से होने वाली पूरी उत्पाद शुल्क आय उपचार के लिए दी जाएगी। हालांकि, उनका कहना था कि अगर राज्य अभी स्थानीय सरकारों से धन लेता है, तो उसे पूरी भरपाई करनी चाहिए, ताकि वे शराब विरोधी नीतियां जारी रख सकें।